भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 15

उत्तर देने की तारीख 3 फरवरी, 2025

सोमवार, 14 माघ 1946 (शक)

हाशिए पर पड़े समुदायों का कौशल विकास

15. श्री विजय बघेलः
श्री दिनेशभाई मकवाणा
श्री पी.पी.चौधरीः
डॉ. के.सुधाकरः
श्री लुम्बा रामः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि औद्योगिक मूल्य-संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) पहल से हाशिए पर पड़े और वंचित समुदाय लाभान्वित हों, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या स्ट्राइव पहल के लिए भविष्य में कोई विस्तार योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त पहल के तहत कोई नए कौशल क्षेत्र या उद्योग शामिल करने की योजना बना रही है;

(घ) कर्नाटक, विशेषकर चिक्काबल्लापुर से प्रशिक्षित किए जा रहे उक्त समुदायों के कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार की ऐसी विभिन्न योजनाओं और नीतियों का ब्यौरा क्या है जिनसे कर्नाटक के उक्त समुदायों के उत्थान और सशक्तिकरण में सहायता मिली है ?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) जी हां। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना को कार्यान्वित किया, जो विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत सरकार की परियोजना थी। स्ट्राइव परियोजना के अंतर्गत कुल 500 आईटीआई (जिनमें 467 सरकारी आईटीआई और 33 निजी आईटीआई शामिल हैं) को उन्नयन के लिए चुना गया।

स्ट्राइव परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सीखने के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, उन्नत और बढ़ाना था, जिससे सीमांत और वंचित समुदायों सहित सभी प्रशिक्षुओं को मदद मिलेगी।

(ख) और (ग) जी नहीं, स्ट्राइव परियोजना दिनांक 31.05.2024 को पहले ही समाप्त हो चुकी है और स्ट्राइव पहल के लिए भविष्य में कोई विस्तार योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) समाज के विभिन्न वर्गों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करता है। कर्नाटक राज्य और चिक्काबल्लापुर जिले में इन स्कीमों से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ इन स्कीमों का विवरण नीचे दिया गया है:

• <u>शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस):</u> कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), कर्नाटक राज्य सहित देश भर के सभी समुदायों के युवाओं को लाभान्वित करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) को कार्यान्वित करता है।

आईटीआई में, 166 एनएसक्यूएफ संरेखित ट्रेडों में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक ट्रेड का एक समर्पित पाठ्यक्रम है। प्रशिक्षण की अवधि आमतौर पर एक और दो वर्षों की होती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को ट्रेडों में बुनियादी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है ताकि प्रशिक्षु को अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार हेतु तैयार किया जा सके।

वर्तमान में, देश में 14,619 आईटीआई स्थापित हैं, जिनमें से 3,316 आईटीआई सरकारी आईटीआई हैं और 11,303 आईटीआई निजी आईटीआई हैं। कर्नाटक राज्य में कुल 1,466 आईटीआई (274 सरकारी आईटीआई और 1,192 निजी आईटीआई) हैं। विगत पांच वर्षों में, कर्नाटक राज्य में वंचित समुदायों के 3,28,073 छात्रों को आईटीआई में प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 5,968 चिक्काबल्लापुर जिले से हैं।

• <u>प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):</u> "कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य कर्नाटक राज्य सहित देश भर के युवाओं को अल्पावधि

प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशल प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य के सीमांत समुदायों से कुल 69,126 लाभार्थियों को प्रमाणित किया गया है, जिनमें से 1253 चिक्काबल्लापुर जिले से हैं।

• <u>जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस):</u> जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम, जिसे प्रारम्भ में 1967 में श्रमिक विद्यापीठ (एसवीपी) के रूप में शुरू किया गया था, का उद्देश्य भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ पंजीकृत सोसायटियों (एनजीओ) के माध्यम से लाभार्थी के पहुँच तक अनौपचारिक तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्व/वैतनिक रोजगार को बढ़ावा देकर घरेलू आय में वृद्धि करना है। जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के निरक्षर, नव-साक्षर और 8वीं कक्षा तक की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। अब तक पूरे देश में जेएसएस स्कीम के अंतर्गत 28.83 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कर्नाटक राज्य में, विगत पांच वर्षों में सीमांत समुदायों से कुल 64,451 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले में कोई कार्यात्मक जेएसएस नहीं है।

• <u>आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता ("संकल्प"):</u> संकल्प परियोजना को विश्व बैंक के सहयोग से एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में प्रारम्भ किया गया था और यह 31 मार्च 2025 को बंद होने वाली है। इसका उद्देश्य संस्थानों को सुदृढ़ करने, बेहतर बाजार संपर्क स्थापित करने और समाज के सीमांत वर्गों को शामिल करने के माध्यम से गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना है। संकल्प परियोजना के राज्य घटक के हिस्से के रूप में, एमएसडीई ने कर्नाटक राज्य को कुल 34.02 करोड़ रुपए (केंद्र और राज्य का हिस्सा) जारी किए हैं। संकल्प परियोजना के परिणाम क्षेत्रों से जुड़ी कुल 67 परियोजनाओं को कर्नाटक राज्य द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जिनमें से 29 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। कर्नाटक में इन परियोजनाओं से वंचित समुदायों के 4000 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से 196 चिक्काबल्लापुर जिले से हैं।

विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य और विशेष रूप से चिक्काबल्लापुर जिले से इन स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए सीमांत समुदायों के व्यक्तियों की संख्या भी नीचे दी गई है:

स्कीम का नाम	**प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या- कर्नाटक राज्य**	**प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या- चिक्काबल्लापुर जिला**
शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम	3,28,073	5,968
प्रधानमंत्री कौशल विकास स्कीम	69,126	1,253
जन शिक्षण संस्थान	64,451	कार्यात्मक जेएसएस की संख्या
संकल्प	4,000	196

*****